अंक 01 ● जून 2022

समाचार पत्रिका

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग (MPSPPC)

समाचार | दृष्टिकोण | अपडेट

संदेश

श्री शिवराज सिंह चौहान
माननीय मुख्यमंत्री
अध्यक्ष, राज्य नीति एवं योजना आयोग

प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित करने के लक्ष्य को आत्मसात करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग, राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इस टीम पर लोक-नीति निर्माण की प्रक्रिया में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने का दायित्व है। प्रादेशिक नीतियों में अंत्योदय की भावना का समावेश कर प्रदेश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में भी आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश को हर दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के महाभियान में पूर्ण तत्परता से सतत् संलग्न "नीति दल" को मेरी शुभकामनाएं।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
उपाध्यक्ष
राज्य नीति एवं योजना आयोग

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग, सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विविध विभागों को सहयोग प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। हम प्रादेशिक अनुसंधान, सहभागिता, ज्ञान व कौशल विकास एवं अन्य संस्थागत योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित कर, प्रदेश की रणनीतिक कार्ययोजना-2030 एवं कार्यात्मक प्राथमिकताओं को सतत् विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की दिशा में प्रयासरत हैं। टीम नीति; प्रदेश एवं केंद्र के साथ साझी रणनीति विकसित कर, विविध परियोजनाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के लिए वित्तीय प्रबंधन एवं लक्षित तकनीकी सहायता प्रदान कर रही हैं।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग, बतौर नोडल संस्था राज्य का प्रतिनिधित्व करती है एवं प्रदेश में केंद्रीय नीति आयोग की क्रियान्वयन संस्था के तौर पर कार्य करती है।

संदेश

मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग एक थिंक टैंक के रूप में प्रदेश के लोक व्यय की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदेश के विभिन्न विभागों के लिए अनुसंधान और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। प्रदेश के विकास हेतु राज्य की सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य नीति एवं योजना आयोग एक नीति संस्थान के रूप में, विभिन्न शोधकर्ताओं, हितधारकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों और अग्रिम पंक्ति के सामाजिक सेवा प्रदाताओं के साथ एक मंच पर परिचर्चा कर, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका अदा करता है।

श्री मुकेश चन्द गुप्ता, IAS
प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लिए नीति एवं योजना सलाहकार की भूमिका निभाता है। राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य नीति एवं योजना आयोग मध्य प्रदेश सरकार के बौद्धिक संवर्ग के रूप में सुशासन के अभिनव तौर-तरीकों की पहचान कर संबन्धित विभागों में इन तौर-तरीकों के प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु रणनीतिक सलाह देने की भूमिका का निर्वहन करता है।

श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, IAS
सदस्य सचिव, राज्य नीति एवं योजना आयोग

आर्थिक महाशक्ति बनने की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को फलीभूत करने के लिए राज्य नीति एवं योजना आयोग एक थिंक टैंक के रूप में विकास के नए क्षेत्रों का सतत् अन्वेषण कर रहा है। एक नीति सलाहकार संस्थान के रूप में हमने, राज्य में ज्ञान एवं नवाचार आधारित सतत् और समग्र विकास के लिए आंतरिक विभागों के साथ-साथ बाहरी हितधारकों के साथ भी सहयोग करना जारी रखा है। मध्य प्रदेश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने हेतु नीति-निर्माण के लिए हम साक्ष्य-आधारित रचनात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

श्री अभिषेक सिंह, IAS
प्रमुख सलाहकार, राज्य नीति एवं योजना आयोग

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग आंकड़े आधारित नीति निर्माण में अपनी परामर्शी भूमिका के माध्यम से राज्य में समग्र विकास में अपना योगदान दे रहा है। मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु, सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु, राज्य नीति एवं योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित है।

श्री पी. सी. बारस्कर
सलाहकार, राज्य नीति एवं योजना आयोग

परियोजना पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं समन्वयन

राज्य परियोजना समीक्षा (प्रगति)

प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विकास संबन्धित परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा करने की अभिनव पहल है – "प्रगति"। इन समीक्षा बैठकों में 5 करोड़ रुपए से अधिक बजट की विविध परियोजनाओं का चुनाव किया जाता है और प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के आधार पर इन कार्यों के भौतिक प्रगति की समीक्षा कर संबन्धित चुनौतियों के त्वरित निराकरण की व्यवस्था बनाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा परियोजनाओं की जिलेवार समीक्षा की जाती है, जिससे अंतर्विभागीय समन्वयन सुगम होता है और परियोजनाओं की प्रगति में तेजी आती है। विविध विभागों से इन परियोजनाओं की प्रगति संबन्धित जानकारियों के एकत्रण, समन्वयन, प्रमाणीकरण एवं प्रस्तुतीकरण की ज़िम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग (MPSPPC) की टीम निभाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 20 अप्रैल 2022 को आहूत की गई 15वीं प्रगति समीक्षा बैठक में भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क परियोजना, भिंड एवं सागर जिले की जलापूर्ति परियोजनाओं, इंदौर की पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना और ग्वालियर जिले की 1000 बिस्तरों वाली अस्पताल निर्माण परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के आधार पर, माननीय मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हुए, विभागीय प्रमुखों को राज्य की जनता के हितों को सर्वोपरि रखकर अंतर्विभागीय समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिये गये।

आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम (ABP)

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम को और भी जमीनी स्तर पर ले जाते हुए, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 2018 में प्रारम्भ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में आकांक्षी विकासखंडों का व्यापक विकास सुनिश्चित करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी अधोसंरचना, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों से जुड़े 75 संकेतकों के आधार पर सभी 50 विकासखंडों में विकास का एक उच्च मापदंड प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। विकासखंड स्तर पर क्रियान्वित की जा रही यह सूक्ष्म स्तरीय विकास पहल, सहयोग और समावेश के सिद्धांत पर आधारित है।

आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के क्रियान्वयन को और भी प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिनाँक 21 मार्च 2022 को प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग प्रमुखों ने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आदरणीय मुख्य सचिव ने आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के परिमापन में प्रयुक्त किए जा रहे विकास सूचकांकों की संख्या 103 को संशोधित कर 75 करने पर सहमति दी एवं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम से संबन्धित भावी कार्य-योजनाओं के निष्पादन हेतु दिशानिर्देश दिये। नवनिर्धारित 75 संकेतकों में स्वास्थ्य क्षेत्र से 22 संकेतक, शिक्षा क्षेत्र से 19 संकेतक, कृषि और संबद्ध सेवाओं के 16 संकेतक, बुनियादी अधोसंरचनाओं के विकास संबन्धित 13 संकेतक, कौशल विकास के लिए 3 संकेतक और सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित 2 संकेतक हैं।

सतत् विकास लक्ष्य (SDGs)

मध्यप्रदेश सामाजिक और आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है। सतत् विकास कार्यक्रम के 6 लक्ष्यों (एसडीजी 6, एसडीजी 7, एसडीजी 11, एसडीजी 12, एसडीजी 15 और एसडीजी 16) में प्रदेश की अग्रणी रैंकिंग है। राज्य ने चार अन्य लक्ष्यों (एसडीजी 3, एसडीजी 5, एसडीजी 8 और एसडीजी 10) के प्राप्ति की दिशा में भी आशातीत प्रदर्शन करते हुए परफॉर्मर श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। राज्य नीति एवं योजना आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट का विभागवार, क्षेत्रवार और संकेतकवार विश्लेषण कर, एक समेकित रिपोर्ट तैयार की है और विभागीय कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट को सभी विभागों के साथ साझा किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्य कार्यक्रम अंतर्गत राज्य की रैंकिंग में सुधार लाना है। SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि अधिकांश संकेतकों को संबंधित विभागों द्वारा अच्छी तरह से संकलित किया जा रहा है, हालांकि; कुछ संकेतक ऐसे भी हैं जिन पर बेहतर काम करने की ज़रूरत है। सतत् विकास कार्यक्रम में राज्य की प्रगति का सटीक आंकलन सुनिश्चित करने के लिए राज्य नीति एवं योजना आयोग (MPSPPC), नीति आयोग की एसडीजी टीम के साथ बैठक करके संकेतकों को परिमार्जित करने की संभावनाओं पर चर्चा करने की योजना बना रहा है।

बोर्ड मीटिंग

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की तीसरी बोर्ड बैठक 16 दिसम्बर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वल्लभ भवन, भोपाल में आयोजित की गयी। बोर्ड की इस बैठक में राज्य नीति एवं योजना आयोग को निर्दिष्ट आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम और सतत् विकास लक्ष्य संबन्धित कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड बैठक में हुई चर्चा और विचार-विमर्श के आधार पर राज्य नीति एवं योजना आयोग देवारण्य नीति, मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन, जल नीति, फसल-विविधीकरण, मिलेट मिशन, कृषि एवं बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, महिला सशक्तिकरण, सार्वभौमिक कौशल शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति जैसे विविध क्षेत्रों में नीतिगत अनुसंधान की पहल कर रहा है। सतत् विकास लक्ष्य रैंकिंग में प्रदेश की स्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से बोर्ड ने संकेतकों के सतत् पर्यवेक्षण एवं संबन्धित विभागों से समन्वयन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है।

रणनीतिक पहल

GSDP कार्य समिति की रिपोर्ट

GSDP कार्य समिति की रिपोर्ट दिनांक 3 मार्च, 2022 को, माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की गई। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश की जीडीपी के आकार में वृद्धि एवं सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने के उपायों की अनुशंसाएं प्राप्त करने हेतु, राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रो. सचिन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में GSDP कार्य समिति का गठन किया गया था। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश चन्द गुप्ता इस कार्य समिति के सदस्य सचिव थे। इस कार्य समिति ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सभी घटकों की गहन समीक्षा करने के बाद पाया कि कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) और निर्यात जैसे क्षेत्र, राज्य की जीएसडीपी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

कार्य समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक दशक के दौरान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 19.10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यहां तक कि कोविड के बीच देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में 19.74% की वृद्धि दर दर्ज की है। GSDP कार्य समिति की रिपोर्ट में प्रदेश के आर्थिक विकास यात्रा के तीन संभावित मार्गों की परिकल्पना की गई है। वर्तमान परिदृश्य और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्य समिति ने अपने विश्लेषण में यह पाया है कि मार्च 2022 में मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 156 बिलियन डॉलर था। यदि अर्थव्यवस्था का विकास वर्तमान गति से ही होता है तो 2025-26 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 230 बिलियन डॉलर की बन जाएगी। अर्थव्यवस्था यदि 'राइजिंग कर्व' (Rising Curve) पथ का अनुसरण करती है तो इस अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 280 बिलियन डॉलर तक का आकार प्राप्त कर सकती है। किन्तु एक तीसरा विकल्प है 'लीप फ्रॉगिंग' अर्थात "बड़ी आर्थिक छलांग" लगाने का। यदि प्रदेश में इस कार्य समिति की 'लीप फ्रॉगिंग' अनुशंसाओं को लागू कर उनका क्रियान्वयन किया जाये तो 550 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार मध्यप्रदेश राज्य 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

मध्यप्रदेश की सांख्यिकी प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए गठित कार्य समिति की रिपोर्ट

मध्यप्रदेश में सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु गठित कार्यसमिति की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को 26 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की गई। मध्यप्रदेश में राज्य और ज़िला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणाली का पेशेवर संचालन और वैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यसमिति का गठन प्रो. अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में

किया गया था। श्री अभिषेक सिंह (प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग) इस कार्यदल के संयोजक हैं। श्री मुकेश चन्द गुप्ता (प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसाओं को राज्य में लागू करने के लिए 29 अप्रैल 2022 को मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन को विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी।

कार्यसमिति ने जीएसडीपी, कीमतों और व्यय के आंकलन के लिए राज्य द्वारा अपनाए गए मौज़ूदा दृष्टिकोण को प्रोन्नत करने; सांख्यिकीय अंकेक्षण के लिए राज्य और जिला स्तर की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने; सांख्यिकी संबन्धित विविध प्रकाशनों को नागरिकों और विशेषज्ञों के लिए अधिक व्यापक, सुलभ और आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए अभिनव तरीके अपनाने एवं डेटा प्रबंधन प्रणालियों के आधुनिकीकरण एवं मानव संसाधन के प्रशिक्षण की अनुशंसाएं की हैं। राज्य में सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए "राज्य सांख्यिकी आयोग की स्थापना" की अनुशंसा भी की गई है।

क्षमता संवर्धन

उड़ीसा का अध्ययन दौरा

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के सलाहकार श्री पी.सी. बारस्कर के नेतृत्व में परामर्शदाताओं का एक दल अध्ययन दौरे के लिए उड़ीसा गया। इस दल ने उड़ीसा सरकार द्वारा चाइल्ड आउटकम बजट एवं सतत् विकास लक्ष्य कार्यक्रम की बजटिंग एवं क्रियान्वयन में प्रयुक्त की जा रही बेस्ट प्रेक्टिसेस का अध्ययन किया।

वर्तमान में राज्य द्वारा, सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जा रहे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय बजटीय आवंटन और विविध योजनाओं के बीच प्रभावी समन्वयन एवं अभिसरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अतः SDG हेतु बजट (SDG Budgeting) पर ध्यान केन्द्रित कर, इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू किए जाने के उद्देश्य से उसका अध्ययन एवं मूल्यांकन किया गया।

SDG बजटिंग के माध्यम से उड़ीसा के विभिन्न विभागों की कार्ययोजनाओं के एकीकरण एवं समन्वयन की दिशा में भी सफलता परिलक्षित हुई है, जो अंततः उड़ीसा राज्य के रैंक में सुधार करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। उड़ीसा के अनुभव के आधार पर; राज्य नीति एवं योजना आयोग की टीम मध्य प्रदेश में भी SDG हेतु बजट (SDG Budgeting) की योजना बना रही है। बजट को इस प्रकार संरेखित करने से सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति राज्य के दृष्टिकोण को और अधिक युक्तिसंगत बनाने में मदद प्राप्त होगी एवं जिन SDG सूचकांकों में राज्य पिछड़ रहा है उनमें अधिक विवेकपूर्ण प्रबंधन और कार्ययोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट (GRB) पर कार्यशाला

संयुक्त राष्ट्र महिला संस्थान के सहयोग से महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश के तत्वाधान में 8 अप्रैल 2022 को "जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य नीति एवं योजना आयोग के परामर्शदाताओं ने भाग लिया।

लैंगिक विश्लेषण के आधार पर GRB सरकारी संस्थानों की नीतियों, योजनाओं, बजट एवं संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया में सुधार लाकर समाज में लैंगिक समानता प्राप्त करने की अवधारणा है।

नीति विश्लेषण एवं अनुसंधान

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग (MPSPPC) ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान (AIGGPA) के साथ मिलकर, प्रदेश की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति का प्रारम्भिक ड्राफ्ट बनाया है। "वैश्विक उत्कृष्टता एवं स्थानीय प्रासंगिकता" के ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को उत्प्रेरित करने वाले पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाने के उद्देश्य से बनाई जा रही इस नीति का क्रियान्वयन राज्य के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक सिद्ध होगा। इस नीति का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तक्षेप के माध्यम से प्रदेश के सतत् विकास और सामाजिक-आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को गति देना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति का लक्ष्य :

- मध्यप्रदेश को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उन्नत करना और राज्य को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 5 में स्थान दिलाना।
- सार्वजनिक/निजी भागीदारी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हस्तक्षेप के माध्यम से रोजगार अवसरों के सृजन को दोगुना किया जाना।
- अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपलब्ध मानव संसाधन में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का विकास कर उनका कौशल संवर्धन करना।
- 'वोकल फॉर लोकल' पर जोर देते हुए पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों के सतत् विकास को बढ़ावा देना।
- अग्रणी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण, अनुकूलन और उपयोग की सुविधा एवं उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना।

राज्य नीति एवं योजना आयोग के परामर्शदाता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) के सुझावों एवं अनुशंसाओं के अनुरूप "विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022" को अंतिम रूप देने की दिशा में अग्रसर हैं।

प्रदेश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को गति देने हेतु माइक्रो-एटीएम की उपयोगिता

देश के प्रत्येक नागरिक तक वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, भारत सरकार की एक अग्रणी प्राथमिकता है। देश के दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं एवं ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स (ATMs) की स्थापना एवं संचालन, तकनीकी एवं वित्तीय नजरिये से बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। अपने पोर्टेबल स्वरूप, अल्प-लागत एवं सहज संचालन जैसे गुणों की वजह से आर्थिक एवं सामाजिक पायदान में सबसे निचले स्तर पर खड़े नागरिकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य की प्राप्ति में माइक्रो एटीएम निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के त्वरित निष्पादन हेतु माइक्रो एटीएम की सघन उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग (MPSPPC) की टीम ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसी कड़ी में तकनीकी का इस्तेमाल कर वित्तीय समावेशन प्राप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधियों के साथ मुंबई में एक परिचर्चा संपन्न हुई। इस परिचर्चा में मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग (MPSPPC) के उपाध्यक्ष, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, डॉ. मनोज गोविल, MPSPPC के सदस्य सचिव, श्री स्वतंत्र कुमार सिंह एवं टीम के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

समेकित जल-नीति 2022

मध्यप्रदेश की वर्तमान जल नीति सर्वप्रथम वर्ष 2003 में बनाई गई थी, जो भारत की राष्ट्रीय जल नीति-2002 पर आधारित थी। विगत वर्षों में देश को बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा है, इसके परिणामस्वरूप जल स्त्रोतों पर दबाव बहुत बढ़ चुका है, भारत की राष्ट्रीय जल नीति-2012 का लक्ष्य, जल संसाधनों पर मानवजनित गतिविधियों के प्रभावों के साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन की वजह से पड़ने वाले प्रभावों को भी प्राथमिकता पूर्वक नियंत्रित करना है। मध्यप्रदेश की जल-सम्पदा को तीन स्त्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है- वर्षा, भूजल और सतही जल (जैसे नदियाँ, तालाब और झीलें)। नदियों में नर्मदा, बेतवा, सोन, ताप्ती, चंबल आदि प्रमुख नदियाँ शामिल हैं। भारत सरकार प्रति व्यक्ति 1700 क्यूबिक मीटर से कम की वार्षिक जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों को तनावग्रस्त जल क्षेत्र और प्रति व्यक्ति 1000 क्यूबिक मीटर से कम वार्षिक जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों को अल्प-जल (पानी की कमी) क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है। इन मापदण्डों के अनुसार, वर्ष 2011 के बाद से ही मध्यप्रदेश पानी की कमी से जूझ रहा है क्योंकि प्रदेश में प्रति व्यक्ति पानी की वार्षिक उपलब्धता 1611 क्यूबिक मीटर है। वर्ष 2031 तक यह आंकड़ा प्रति व्यक्ति 1244 क्यूबिक मीटर तक गिर जाने की आशंका है। जल-क्षरण की यह प्रवृत्ति जारी रही तो वर्ष 2050 तक मध्य प्रदेश में पानी की विकराल समस्या उत्पन्न हो सकती है। जल की सीमित उपलब्धता एवं जलवायु परिवर्तन-प्रेरित कारकों के प्रकाश में समस्त गतिविधियों हेतु जल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करना एक दुष्कर कार्य है।

प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रादेशिक जल-नीति बनाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग ने प्रदेश की वर्तमान जल-नीति का अध्ययन एवं विश्लेषण कर एक नई जल नीति का प्रारूप तैयार किया है। यह नीति जल संवर्धन के उपाय करके प्रदेश को जल-तनावग्रस्त राज्य से जल-अधिशेष राज्य में परिवर्तित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। जल नीति के मसौदे में कृषि, ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति और उद्योगों को जलापूर्ति जैसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं। जल संसाधनों के प्रबंधन से संबन्धित मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के साथ परामर्श कर, डाटा संग्रहण एवं विश्लेषण करने के बाद इस नीति मसौदे में अनुशंसाएं की गई हैं। यह नीति डेटा, अनुसंधान और प्रशिक्षण संसाधनों की साझा उपयोगिता पर बल देती है। अपशिष्ट जल को एक संसाधन के रूप में देखते हुए इस नीति मसौदे में अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्नत तकनीकों और सूचना प्रणालियों की उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने की अनुशंसा की गई है। वर्तमान में नीति आयोग दल के सदस्य जल-नीति से संबन्धित विविध विभागों एवं हितधारकों से समन्वयन स्थापित कर आवश्यक डाटा एकत्रित कर विषय-विशेषज्ञों के विचार समायोजित कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश मिलेट मिशन 2022

मिलेट्स को सामान्यतः सुपरफूड के रूप में देखा जाता है, जो अनेक आवश्यक विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मध्यप्रदेश में मिलेट मिशन पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा पूर्व से कार्य किया जा रहा है। मिलेट्स के उपार्जन, प्रयोग एवं वृहद् बाजार बनाने तथा प्रदेश में फसल विविधीकरण की योजना के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और मंडी बोर्ड के सहयोग से मध्यप्रदेश मिलेट मिशन का मसौदा तैयार किया है। मिलेट मिशन का उद्देश्य लघु मिलेट्स (कोदो-कुटकी) का प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन संबंधी नीति बनाकर किसानों की आय में वृद्धि के अवसर उत्पन्न करना है। साथ ही इन लघु मिलेट्स संबंधी संस्थाओं को भी बढ़ावा देना है। यह प्रदेश स्तर पर भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों को मजबूत करने संबन्धित नीतियों

पर भी ध्यान केन्द्रित करता है। मध्यप्रदेश सरकार के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर इस मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोदो-कुटकी को एक ब्रांड के अन्तर्गत स्थापित करने की परिकल्पना भी की गई है।

मध्यप्रदेश सहकारिता नीति 2022

सहकारिता समाज के समग्र एवं सर्वव्यापी विकास करने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। पारस्परिक सहयोग, स्वावलंबन और स्वदेशी जैसे मानवीय सिद्धांतों और भारतीय मूल्यों पर आधारित यह जन-आंदोलन 'अंत्योदय' की अवधारणा को साकार करते हुए प्रदेश के सर्व-समाज का और विशेष रूप से कमजोर वर्गों का सामाजिक-आर्थिक विकास रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ समय से नए क्षेत्रों में सहकारिता मॉडल अपनाते हुए नवाचारों के माध्यम से वृहद् स्तर पर रोजगार सृजन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाकर समाज के अंतिम पायदान में खड़े लोगों का विकास सुनिश्चित करने हेतु नए क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों का गठन करने एवं वर्तमान में कार्यरत सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं क्षमतावान बनाने की आवश्यकताओं पर भी मंत्रणाएँ हो रही हैं। तदानुसार, राज्य नीति एवं योजना आयोग ने प्रदेश के सहकारिता विभाग के साथ मिलकर विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों से परामर्श की एक लंबी श्रृंखला के बाद मध्यप्रदेश सहकारिता नीति का प्रारूप तैयार किया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को आवश्यक समर्थन, प्रेरणा और सहायता देकर इन्हें स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर बनाकर इनका सर्वांगीण विकास करना है ताकि प्रदेश की सहकारी संस्थाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले ऐसी जन-भागीदारी केंद्र के रूप में उभर सकें जो अपने सदस्यों एवं लक्ष्यों के प्रति अधिकाधिक जवाबदेह हों।

मध्यप्रदेश सेमी-कंडक्टर निवेश नीति 2022

सेमीकंडक्टर्स/ सिलिकॉन फोटोनिक्स (SiPh)/ सेंसर (MEMS) फैब्स की उत्तरोत्तर बढ़ती हुए वैश्विक मांग को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश एक विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर क्लस्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए निवेश आकर्षित करने की आकांक्षा रखता है। प्रदेश में फैब्स और सेमीकंडक्टर ATMP/OSAT सुविधाओं से युक्त एक एकीकृत मूल्य-श्रृंखला बनाने के उद्देश्य से भविष्य की कार्ययोजनाओं का एक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत्:

- आधुनिक उपकरणों से युक्त FAB, ATMP-OSAT तथा उन्नत प्रशिक्षण/कौशल केन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि का प्रावधान।
- उद्योग, अकादमिक/अनुसंधान संगठनों और राज्य प्रशासन के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए एक नोडल एजेंसी का गठन जो निवेशकों की हर संभव सहायता करेगा।
- विभिन्न वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
- संभावित परियोजनाओं की गैप फंडिंग का आंकलन कर बहुपक्षीय वित्तीय एजेंसियों से समन्वयन स्थापित कर वित्त-प्रबंधन करना।

मध्य प्रदेश ATMP-OSAT निवेश नीति- 2022 के कार्यान्वयन के लिए उद्योग नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग (DIPIP) नोडल एजेंसी होगा। मध्यप्रदेश सेमी-कंडक्टर निवेश नीति का मसौदा तैयार है, जिसकी समीक्षा नीति आयोग, दिल्ली के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत एवं अन्य संबंधित विभागों के द्वारा की जा रही है।

राज्य की जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप

राज्य में मौजूद वर्तमान जैव-औद्योगिक क्षमताओं एवं प्रस्तावित जैव-प्रौद्योगिकी इकाइयों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अन्य तकनीकी प्रक्षेत्रों से तालमेल बनाकर राज्य में नवाचार का वातावरण निर्मित कर, मध्यप्रदेश को जैव-विज्ञान उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के अग्रणी वैश्विक प्रदाता के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस प्रयास करने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। लक्षित जैव अर्थव्यवस्था रणनीति बनाकर राज्य की घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने एवं जैव-अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाने के उद्देश्य से राज्य नीति एवं योजना आयोग जैव-अर्थव्यवस्था रोड-मैप की परिकल्पना तैयार कर रहा है।

राज्य सरकार, प्रदेश का सामाजिक-आर्थिक विकास एवं आजीविका के अवसरों में विस्तार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के जैव-संसाधनों का समुचित उपयोग करने के साथ ही साथ प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु भी प्रतिबद्ध है। हाल के दशकों में, जैव-विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में उभरा है। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए अभूतपूर्व संकट की वजह से औषधि निर्माण संबन्धित नवाचार, अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों में निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। इस अवधि में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने में वैक्सीन उद्योग ने अद्वितीय भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय स्तर पर जैव-अर्थव्यवस्था का आकार 80.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% है। वर्ष 2025 तक लक्षित 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय लक्ष्य में जैव-अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी 150 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाने की संभावनाएं हैं।

वर्ष 2025 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 550 बिलियन डॉलर के उच्च आयाम तक पहुंचाकर 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय लक्ष्य में मध्यप्रदेश अहम भूमिका निर्वहन करने की आकांक्षा रखता है और इस आकांक्षा को फलीभूत करने के लिए लॉन्च किए गए रोड मैप में भी जैव-अर्थव्यवस्था क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में रखा गया है। अत: मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा शासकीय विभागों, शिक्षा जगत एवं उद्योग क्षेत्र के साथ समन्वय एवं संबंधित हितधारकों के परामर्श करके मध्यप्रदेश की जैव अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रणनीति बनाने की कवायद शुरू की गई है। मध्यप्रदेश की जैव अर्थव्यवस्था को विकसित करने की रणनीति का मुख्य फोकस; नवाचारों, कुशल जनशक्ति के विकास, शिक्षा, अनुसंधान एवं उद्यमिता की भावना को बल देते हुए जैव-विज्ञान आधारित औद्योगिक गतिविधियों के निष्पादन के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने पर रहा है।

देवारण्य योजना

मध्यप्रदेश में आयुष आधारित औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने 'देवारण्य योजना' बनाई है। यह योजना राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। राज्य में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन में स्वसहायता समूहों की भी महती भूमिका रहेगी। इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आयुष विभाग, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, पर्यटन विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग और जनजातीय कार्य विभाग मिलकर मिशन मोड में काम कर रहे हैं।

देवारण्य के जरिये आयुष को पर्यटन से जोड़ने की भी योजनाएँ हैं। देवारण्य योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं:

- आयुष उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग पूरी करने के लिए राज्य की कृषि में औषधीय पौधों की खेती का हिस्सा बढ़ाना।
- जनजातीय आबादी का आर्थिक विकास सुनिश्चित कर राज्य के आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना।
- सीमांत किसानों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके उन्हें आजीविका के बेहतर विकल्प प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करना।
- राज्य में पारंपरिक औषधीय पौधों के संरक्षण में योगदान देना।

प्रमुख कार्यक्रम

बजट पर चर्चा

माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर दिनांक 14 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रादेशिक बजट पर चर्चा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने बजट और बजट के पीछे के विजन पर सम्बोधन दिया। इसके बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा बजट पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। राज्य नीति एवं योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने "आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का बजट" विषय पर कैबिनेट मंत्रियों और प्रदेश के विधायकों के साथ चर्चा की।

सिविल सोसाइटी संगठनों (CSO) का समागम

राज्य नीति एवं योजना आयोग तथा जन अभियान परिषद के समन्वय से, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान (AIGGPA) के तत्वाधान में दिनांक 8-9 अप्रैल, 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs) की दो दिवसीय सम्मेलन सभा आयोजित की गई। इस सम्मेलन में संस्थानों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच अनुभव साझा कर, प्रदेश के सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में गैर शासकीय संस्थाओं की सहभागिता विषय पर बौद्धिक-विमर्श हुआ।

इस सम्मेलन का उद्देश्य, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका, विकास पत्रकारिता और बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में बेस्ट प्रेक्टिसेस को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयित करने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों और सरकार के बीच सहयोग की संभावनाएं तलाशनी थी। इस CSO सम्मेलन में विविध NGOs, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों और जन अभियान परिषद (JAP) ने भाग लिया।

CSO सम्मेलन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार, CSO,

बौद्धिक संस्थाओं और अन्य एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट तौर पर चिन्हित किए जाने एवं सभी विकास एजेंसियों के बीच सहयोग की अवधारणा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सहयोग और समन्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध उन्नत संसाधनों और प्रौद्योगिकियों पर भी चर्चा हुई। नई पीढ़ी के बीच विकासवादी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्था (AIGGPA) ने CSO सम्मेलन की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सभी प्रतिभागियों के साथ साझा की है तथा CSOs के माध्यम से क्रियान्वयित होने वाली शासकीय जनकल्याणकारी परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना भी तैयार की गई है।

इसके अलावा राज्य में सतत विकास लक्ष्यों पर काम कर रहे जमीनी स्तर के संगठनों के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक CSO कार्य दल का भी गठन किया गया है।

संवाद सत्र

पचमढ़ी में दिनांक 22-23 अप्रैल 2022 को दो दिवसीय कार्यशाला "चिंतन-2022" का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वित्त विभाग द्वारा "$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय लक्ष्य में मध्य प्रदेश का योगदान" विषय पर प्रस्तुति दी गई जो राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रो. सचिन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित GSDP कार्य समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी।

आयुष निवेश एवं नवाचार संगोष्ठी (20-22 अप्रैल, 2022), गांधीनगर, गुजरात

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में दिनांक 20-22 अप्रैल, 2022 के दौरान आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने दिनांक 20 अप्रैल 2022 को उक्त शिखर सम्मेलन में बतौर संसाधन विशेषज्ञ (रिसोर्स परसन) सहभागिता की। इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत "राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों की पहल प्रोत्साहन, नवाचार और नीतियां" सत्र में मध्य प्रदेश राज्य औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने देवारण्य योजना पर प्रस्तुति देकर मध्यप्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया। देवारण्य योजना का उद्देश्य औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देकर प्रदेश के सीमांत जनजातीय समाज को आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

अतिथि लेख

नीति एवं नियोजन : नगरीय विकास के ध्वजवाहक

श्री हितेश वैद्य
निदेशक
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान,
नई दिल्ली

भारत एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है। भारत में गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली, लोक स्वास्थ्य और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु नगरीकरण प्रक्रिया का बहुत महत्व है। भविष्य में भारतीय नगर ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकें, यह तय करने के लिए हमें बेहतर योजनाएँ बनानी होंगी। अगले 15-20 वर्षों में हमें अनेकानेक चुनौतियों का सामना करना होगा, पर यह चुनौतीपूर्ण कालखंड हमें सर्वव्यापी-सर्वसुलभ आवासीय सुविधाएं (हाउसिंग फॉर ऑल), लोक परिवहन, पेयजल सुविधाएँ, अपशिष्ट निस्तारण और दूषित जल के शोधन जैसे जनकल्याणकारी क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से समाधान ढूँढने के असीमित अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं।

तकनीकों की उपलब्धता ने नवाचार के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में सुगमतापूर्वक मूलभूत नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई रोचक विकल्प उत्पन्न कर दिये है।

भारत की नगरीय व्यवस्था में संस्थानों की बहुलता और इन संस्थानों के कार्यक्षेत्रों में साम्यता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न संस्थानों द्वारा विश्वस्तरीय नगरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु किये जाने वाले नीतिगत परियोजनाओं की परिकल्पना, डिजाइनिंग एवं क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं में सहयोग, समन्वय और एकीकरण लाने की आवश्यकता है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही नगरीय विकास के क्षेत्र में उत्तरोत्तर शोध के माध्यम से विशेषज्ञता हासिल करने की आवश्यकता है।

21वीं सदी की नगरीकरण की प्रक्रिया को सफल और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने हेतु नई नीतियों के साथ ही नई तकनीकी विधाओं और नवीन प्रशासनिक संस्थानों के निर्माण की भी आवश्यकता है।

जनभागीदारी, विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता एवं स्थानीय नगरीय निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित कर, नगरीकरण की आसन्न चुनौतियों का समाधान ढूंढा जाना चाहिए।

आयोग की सहभागिता

बैठक एवं सम्मेलन

- लखनऊ में आयोजित सातवें राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन – "सहकार भारती" में सहकारिता क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के साथ विमर्श में भागीदारी।
- बालाजी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉ. एस.आर. राव के साथ बंगलुरु (कर्नाटक) में जैव-विज्ञान नीति पर परिचर्चा।
- नीति आयोग के सदस्य श्री वी.के. सारस्वत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में मध्यप्रदेश की सेमीकंडक्टर निवेश नीति के प्रारूप पर चर्चा।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ सलाहकार, श्री अखिलेश गुप्ता के साथ मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति के मसौदे पर नई दिल्ली में चर्चा।
- भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक श्री सतीश मराठे के साथ मुंबई में राज्य की सहकारिता नीति पर परिचर्चा।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संस्थान (UNFAO) के मूल्य श्रृंखला विशेषज्ञ, श्री रमन आहूजा के साथ मध्य प्रदेश मिलेट मिशन के मसौदे पर नई दिल्ली में बैठक।

अन्य

- राज्य नीति एवं योजना आयोग, मध्यप्रदेश में कोल गैसीफिकेशन प्लांट की स्थापना में नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की सहायता कर रहा है। राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने के साथ ही साथ यह परियोजना, राज्य के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत भी निर्मित करेगी।
- राज्य नीति एवं योजना आयोग प्रदेश के लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने की दिशा में अनवरत प्रयासरत है ताकि मौजूदा वेयरहाउसिंग सुविधाओं को सुधारकर एक प्रभावी इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) व्यवस्था निर्मित की जा सके।
- ट्रांसजेंडर समाज के कल्याणार्थ होने वाली राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय परामर्श के लिए डेटा संग्रहण।
- मध्यप्रदेश मिलेट मिशन के संदर्भ में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग तथा मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक।
- जल नीति के संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक।
- मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से राज्य नीति एवं योजना आयोग ने पार्वती जलाशय को मछली उत्पादन के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर आधारित परियोजना विकसित की है।
- मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग में इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

"साल में दो दिन ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते - बीता हुआ कल और आने वाला कल"

MPSPPC टीम

योगेंद्र श्रीवास्तव

ऋषि मौर्य

प्राची बोहरे जोशी

राजकमल गौतम

पंकज कुमार नाईक

डॉ. हेमंत सिंह

शिवम के. कंथारिया

डी.एस.रावत

योगराज कोसे

रख्शिंदा अली

संजय दुर्गे

आशीष कुमार सोनी

एस.एन.शर्मा

अनीष गजभिये

गौरव कुशवाह

केशव चौधरी

रवि सोनी

तरुण जनोरिया

हेमंत धौलियां

MPSPPC नीति दल

अभ्युदय झा

अभिषेक भार्गव

अभिषेक मालवीय

अच्युत जोशी

डॉ. आकांक्षा चंद

अमिया शंकर

असित प्रकाश

भानु बित्रा

गौरव थापक

डॉ. ईश गुप्ता

कन्हैया समाधिया

कोमल मिश्रा

कुमार रतन

डॉ. नेहा गुप्ता

प्रशंसा दीक्षित

प्रीति तिवारी

राजदीप सिंह

सुमिता सोनी

सुनील कुमार

विपुल सिंघल

विवेकानंद झा

विषय वस्तु

परियोजना पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं समन्वयन 03
- राज्य परियोजना समीक्षा (प्रगति)
- आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम (ABP)
- सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

बोर्ड मीटिंग 04

रणनीतिक पहल 05
- GSDP कार्य समिति रिपोर्ट
- मध्यप्रदेश की सांख्यिकी प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए गठित कार्य समिति की रिपोर्ट

क्षमता संवर्धन 06
- उड़ीसा का अध्ययन दौरा
- जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट (GRB) पर कार्यशाला

नीति विश्लेषण एवं अनुसंधान 07
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति
- प्रदेश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को गति देने हेतु माइक्रो-एटीएम की उपयोगिता
- समेकित जल नीति
- मध्यप्रदेश मिलेट मिशन
- मध्यप्रदेश सहकारिता नीति
- मध्यप्रदेश सेमी-कंडक्टर निवेश नीति
- राज्य की जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप
- देवारण्य योजना

प्रमुख कार्यक्रम 11

अतिथि लेख 13

आयोग की सहभागिता 14

प्रकाशन 16

संकलन एवं सम्पादन :
डॉ. हेमन्त सिंह, कन्हैया समाधिया, विवेकानंद झा
मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग

डिज़ाइन :
प्रशंसा दीक्षित
मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग

प्रकाशन

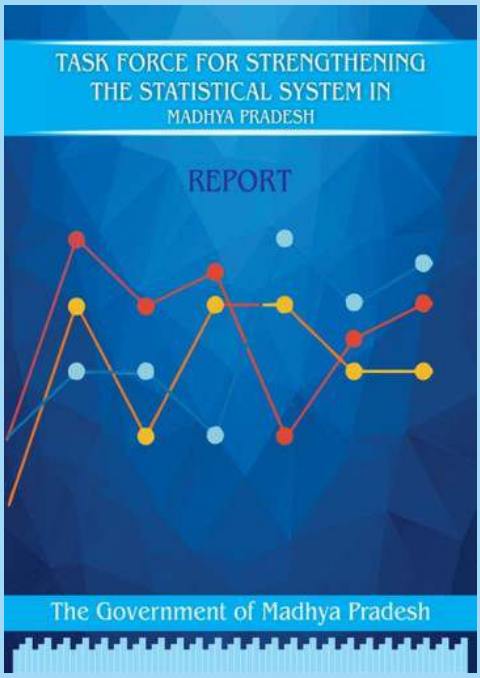

कुंडू कार्य-दल की रिपोर्ट : "मध्यप्रदेश की सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढीकरण" (यहाँ क्लिक करें)

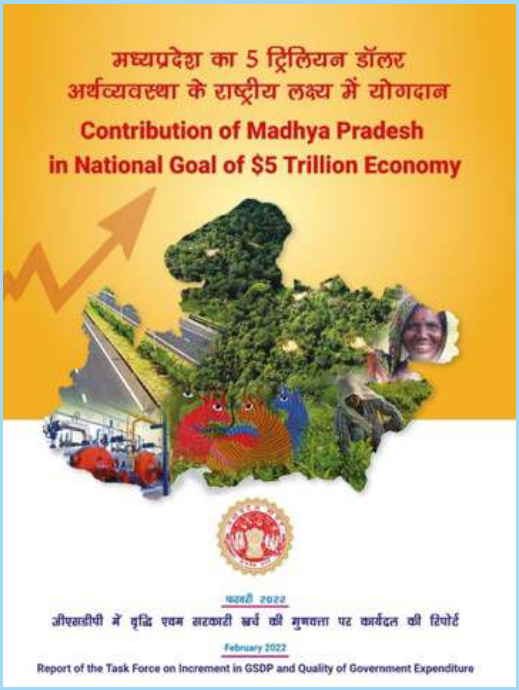

GSDP कार्य-दल की रिपोर्ट: "5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय लक्ष्य में मध्यप्रदेश का योगदान" (यहाँ क्लिक करें)

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग
राजीव गांधी परिसर, प्लाट नं. 35, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)-462 002
दूरभाष : +91 755-2551456, 2551564, 2551135
Email: spb@nic.in, Website: www.mpplanningcommission.gov.in, Twitter : @mpniti

Issue No. 01 ● JUNE 2022

NEWS LETTER

Madhya Pradesh State Policy & Planning Commission (MPSPPC)

NEWS | VIEWS | UPDATES

Message

Shri Shivraj Singh Chauhan
Hon'ble Chief Minister
Chairman, MPSPPC

Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission serves as a think tank of the Government of Madhya Pradesh with an aim of creating a bright future of the State. MPSPPC is working as a nodal agency for catalyzing economic development and fostering cooperative federalism through the involvement of State Government Departments in the public policy-making process using a bottom-up approach. My best wishes to the State Policy and Planning Commission team for their dedicated and continuous efforts in making Madhya Pradesh Atmanirbhar.

Prof. Sachin Chaturvedi
Vice Chairman, MPSPPC

Madhya Pradesh is committed to supporting its line ministries to achieve the Sustainable Development Goals. Our approach is to align the action plan/ strategy 2030 and its operational priorities with the SDGs through research, collaboration, knowledge sharing, capacity building and working in partnership with other institutions. These may include projects linked to SDGs; State Partnership Strategies reflecting national SDG priorities; mobilizing SDG finance through projects and providing targeted technical assistance.

Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission acts as State's nodal agency for implementation of directions and guidelines issued by NITI Aayog, Government of India.

Message

Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission works as a think tank of Madhya Pradesh Government which provides advocacy and performs research for different departments of the State to improve the quality of government expenditure. As a policy institution, MPSPPC continues to bring together researchers, stakeholders, policy makers, academicians, subject matter experts and front line social service providers for strengthening the statistical system in the State to support evidence based policy formulation for the development of Madhya Pradesh.

Shri. Mukesh Chand Gupta, IAS
Principal Secretary, Department of
Planning, Economics & Statistics

State Policy and Planning Commission acts as a planning and policy advisor to different government departments and public undertakings. With the aim of creating a bright future for the state, the commission identifies the efforts being made for good governance and innovative practices and provides strategic advice to the concerned departments for their expansion and replication.

Shri. Swatantra Kumar Singh, IAS
Member Secretary, MPSPPC

Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission, as a think tank, continues to explore the new areas of growth for defining and shaping India's aspiration to become an economic super-power. As a policy advisory institution, we collaborate with internal departments as well as external stakeholders for knowledge-based and innovation-led sustainable and holistic development of the state. We are adopting innovative evidence-based approaches and creative strategies for devising policies to ascend the new heights of prosperity in Madhya Pradesh.

Shri. Abhishek Singh, IAS
Principal Advisor, MPSPPC

Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission with its data driven approach and advisory, is playing an integral role in the policy making for the state. To make long term sustainable impact and benefits for the tribal community. MPSPPC is constantly supporting the initiatives led by the state government for the development of tribal areas.

Shri. P. C. Baraskar
Advisor, MPSPPC

Monitoring, Evaluation and Co-ordination

State Project Review (Pragati)

Pragati is a unique initiative of the Madhya Pradesh Government as it uses MIS for monitoring and supervision of infrastructural project's progress in the state. District-wise review of projects by the Hon'ble Chief Minister facilitates interdepartmental coordination and expedites the project progress. All the infrastructural projects of more than 5 crores are being reviewed under this initiative periodically.

Under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Minister, the 15th review of infrastructural projects was done on 20th April 2022. Based on the review, the Hon'ble Chief Minister directed the concerned departments to expedite the construction works and accomplish all projects within the stipulated timeline.

The 15th Pragati review covered infrastructure projects namely Global Skill Park project, Bhopal; Water Supply project in Bhind and Sagar districts, Power Transmission System Strengthening project, Indore and the 1000 Beds Hospital Project by Public Work Department in Gwalior district. In the Pragati review done in May, 2022 twenty four districts were reviewed.

Aspirational Block Programme (ABP)

Launched in the year 2018 in Madhya Pradesh, the Aspirational Block Programme (ABP) aims at the comprehensive development of aspirational blocks in the state. Based on 75 indicators from education, health, agriculture, infrastructure, skill development and financial inclusion, all 50 blocks are trying to achieve a benchmark of development. This micro-level development initiative is based on the principle of collaboration and convergence at the Block level.

Existing 103 indicators of ABP were reviewed by MPSPPC in consultation with various line departments. In order to make the APB monitoring more comprehensive and progressive, the indicators have been revised to 75 development indicators.

There are 22 indicators from the Health sector, 19 indicators from the Education sector, 16 indicators from Agriculture and Allied services, 13 indicators for Infrastructure development, 3 indicators for Skill Development and 2 indicators related to Social and Financial inclusion.

A review meeting under the chairmanship of Shri Iqbal Singh Bains, Hon'ble Chief Secretary, for finalizing the revised ABP indicators was held on 21st March 2022.

Sustainable Development Goals (SDGs)

As per the SDG India Index report (2020-21) of NITI Aayog, Madhya Pradesh is in the front runner category in SDG 6, SDG 7, SDG 11, SDG 12, SDG 15 and SDG16. The state scored decently in four goals (SDG 3, SDG 5, SDG 8, and SDG 10) and it is in the performer category. With an objective to improve Madhya Pradesh's ranking at the National Level, MPSPPC has conducted department wise, sector-wise and indicator wise analyses of the SDG report. Most of the indicators are being captured well by relevant departments, however, there are some indicators which need to be worked upon. MPSPPC is planning to have a discussion with Niti Aayog for updating the indicators so that the state's progress in SDGs is reflected more accurately. The consolidated report along with the mapping of schemes has been shared with departments to develop their action plan on data updating. The reconciliation work is in progress.

Board Meeting

The 3rd Board Meeting of Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission was held on 16th December 2021 under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister at Vallabh Bhawan, Bhopal. In this board meeting, MPSPPC's mandates related to Aspirational District Programme, Aspirational Block Programme and Sustainable Development Goals were deliberated. Based on the discussions and deliberations of the Board, MPSPPC is taking up various policy research initiatives such as the Devaranya Scheme, Co-operative movement in Madhya Pradesh, Water Policy, Crop-diversification, Millet Mission, Agro and Horticulture, Food Processing, Women Empowerment, Universalisation of Life Skill Education, Science, Technology and Innovation Policy.

Strategies and Reforms

GSDP Task Force Report

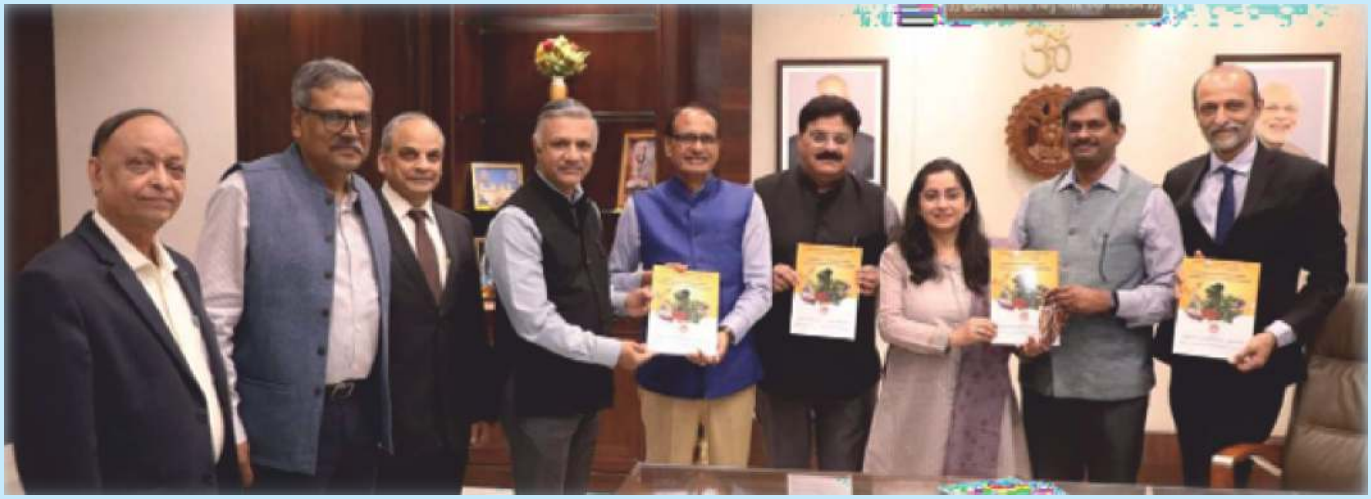

The Report of GSDP Taskforce was presented to Hon'ble Chief Minister on 3rd March, 2022.

This Taskforce was constituted under the Chairmanship of Hon'ble Vice Chairman, MPSPPC to provide recommendations for increasing the size of GSDP and for improving the quality of Public Expenditure of Madhya Pradesh. Shri Mukesh Chand Gupta (PS, Planning, Economics and Statistics) was the Member Secretary for this Task force. The Taskforce identified agriculture, MSMEs and Exports as potential sectors which can contribute substantially to increase the GSDP of the state.

The Taskforce highlighted that the economy of Madhya Pradesh has been growing at 19.1% per annum during the last decade. Despite the nationwide lockdown amid Covid-19, the economy of Madhya Pradesh has been growing at 19.74% per annum during 2021-22. The GSDP Taskforce report envisages three paths through which Madhya Pradesh can move in its developmental journey, aiming at its own contribution towards the national endeavor for achieving a $ 5 Trillion economy status.

The present scenario puts forth an opportunity for Madhya Pradesh to adopt the third approach of "Leap-frogging" which will catapult it from a $ 122 billion economy (9.17 lakh crore) to a $550 billion economy (41.30 lakh crore). Based on the recommendations of the Taskforce, department-wise action plan has been prepared for further actions.

Strengthening Statistical System in Madhya Pradesh - Taskforce Report

The report of the Taskforce on Strengthening Statistical System in Madhya Pradesh was presented to the Hon'ble Chief Minister on 26th February 2022. This Taskforce was constituted for Professional and Scientific Strengthening of the Statistical System at the State and the District level in Madhya Pradesh.

This Taskforce was constituted under the Chairmanship of Prof. Amitabh Kundu and Shri Abhishek Singh (Principal Advisor, MPSPPC) was

the Convenor for this Taskforce. Shri Mukesh Chand Gupta (PS, Planning, Economics and Statistics) shared the detailed action plans to Hon'ble Chief Secretary, GoMP on 29th April 2022 to implement the recommendations of the Taskforce in the state.

The Taskforce recommended upgrading the current approach adopted by the state for estimating GSDP, prices and expenditure; revamping the current administrative set-up at the state and the district level; adopting new and innovative ways to make publications comprehensive, accessible and understandable to the civilians and experts alike and modernising the data management systems. One of the key recommendations of the Taskforce is to establish State Statistical Commission for strengthening the statistical system in the state.

Capacity Building

Exposure visit to Odisha

A team of consultants led by Shri. P.C. Baraskar, Advisor, MPSPPC went for an exposure visit to Odisha. The objective of the exposure visit was to learn about the best practices of the Odisha Government in the field of Child Outcome Budget and SDGs Budgeting.

In the present scenario, there is a growing focus on ensuring the effective integration of SDGs into national/state budgetary and planning processes. The primary objective of the budgetary process is to evaluate State's commitment to the SDGs and their targets. The team observed that in Odisha, SDG budgeting has been given its due emphasis, which is very important for achieving the goals at the state level. Apart from this, SDG budgeting is also helpful in bringing unity of objective across departments which is ultimately helpful in improving the state's rank/performance.

Based on Odisha's experience, the MPSPPC team is planning to conduct SDG budget exercises in Madhya Pradesh as well. This exercise will help to rationalize and reinvigorate the state's approach, by devising new initiatives, where the state is lagging and/ or prudent management and implementation of existing schemes are required. The links between budgets and the SDGs, especially the state indicator framework, can reveal the progress of the state towards achieving the SDGs and help assess the government's performance.

Workshop on Gender Responsive Budgeting

On 8th April 2022, a workshop was organised on the issue of "Gender Responsive Budgeting", by the Women and Child Development department, Madhya Pradesh in collaboration with UN Women. MPSPPC participated in the workshop. GRB brings gender analysis into policies, plans, budgets and programmes of government institutions to improve the allocation of resources for achieving gender equality.

Policy Advisory and Research

Science, Technology & Innovation Policy 2022

MPSPPC in coordination with AIGGPA prepared a zero draft for Science, Technology & Innovation Policy. This policy aims to develop a Science, Technology and Innovation (STI) ecosystem in Madhya Pradesh that will ameliorate the scenario of technological self-reliance i.e. Aatmanirbhar Madhya Pradesh, which in turn will drive economic growth of the state via global excellence and local relevance. It focuses on sustainable growth and socio-economic improvement through science and technology interventions.

The vision of the STI policy aims:

- To elevate Madhya Pradesh as a frontier state in the field of Science, Technology and Innovation and place the State among the top 5 scorers in India Innovation Index.
- To generate employment opportunities through Science, Technology & Innovation intervention in various sectors by public/private partnership.
- Developing the scientific and technological capacity to provide a highly skilled human resources for increased productivity in the economy.
- To promote the sustainable development of natural resources by adopting the Traditional Knowledge System (TKS), with emphasis on 'vocal for local'.
- Fostering national and international linkages for enhanced technology transfer to facilitate the acquisition, adaptation and utilization of frontier technology.
- The policy draft is under evaluation for recommendations and suggestions by the MP Council of Science and Technology (MPCST), Bhopal and the Department of Science & Technology, GoI.

Ensuring last-mile delivery of financial services through Micro ATMs

The provision of financial services to every citizen of the country is a priority of the Government. The expansion and promotion of micro ATMs among the rural population in remote areas, where setting up ATMs is technically and financially challenging, can be a game-changer in achieving the goal of providing last-mile delivery of financial services in India.

MPSPPC is working on a policy framework to expand Micro ATM services in rural areas to ensure prompt delivery of financial services.

"There are two days in the year that we can not do anything, yesterday and tomorrow."

Integrated Water Policy 2022

The current water policy of Madhya Pradesh, State Water Policy (MPSWP) 2003, was aligned with the National Water Policy of India, 2002. Since then, the country has faced major changes that have stressed the water sources indiscriminately. The National Water Policy of India, 2012 was notified to ensure that climate change-induced stresses along with the impacts of anthropogenic activities on the water are actively addressed and prevented. MP receives all its water from three sources majorly- rain, groundwater, and surface water bodies such as seasonal rivers and lakes. major rivers are Narmada, Betwa, Son, Tapi, Chambal, etc. The Government of India considers any region with less than 1700 cubic metres per person annual water availability as water-stressed and less than 1000 cubic metres per person annual water availability as water-scarce. Since 2011, MP has been water-stressed as the annual per capita availability of water is 1611 cubic metres. Considering constant annual water availability, this is projected to fall up to 1244 cubic metres per capita by 2031. If the trend continues, this could lead to the state becoming water-scarce by 2050. with such limited availability of water, all the users and activities must get sufficient water while simultaneously ensuring the resilience of the water resource system towards climate change-induced impacts.

The MP State Water Policy prepares a strategy to ensure that the state transitions from a water-stressed state to a water surplus state. The water policy draft covers domains of agriculture, rural water supply, urban water supply and industries. The current recommendations are developed based on data collection, meetings, and consultations with various departments of the Government of MP, parastatal agencies, and NGOs. The policy lays focus on information and use of advanced techniques and information systems for mapping and sharing data, research and training, seeing wastewater as a resource and promoting recycling and reuse of wastewater (as suggested in MP State Policy for Waste Water Recycle & Reuse and Fecal Sludge Management, 2017), institutional changes (such as in MP Bhumi Vikas Rules 2012), resource management through aquifer mapping, water tariffs and pricing, etc.The objective of making MP water surplus can be achieved through the optimal usage of available water sources, ensuring active rain-water harvesting to recharge aquifers, promoting the reuse of treated domestic and industrial wastewater for non-potable uses and the use of technology and innovation to support the activities of water conservation.

Madhya Pradesh Millet Mission 2022

Millets are often referred to as superfood and their products can be seen as an approach to sustainable agriculture and a healthy world. Millets, in general, are hardy crops which provide many essential vitamins and micro nutrients.

MPSPPC is working with Farmer Welfare and Agriculture Development Department, MP State Agriculture Marketing (Mandi Board) and contributing to the Madhya Pradesh Millet Mission policy draft. The objective of the Millet Mission is to promote minor millets (Kodo-Kutki) along with processing, value addition and marketing to provide remunerative prices to farmers and the federation for these minor millets. It also focuses on strengthening the storage and processing units across state, to provide

remunerative prices to farmers and the federation for these micro millets. The draft policy envisages establishing Kodo-Kutki as a brand in the state. Key inputs have been received from the Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Govt of Madhya Pradesh.

Madhya Pradesh Cooperative Policy 2022

Cooperatives are a strong and effective medium of ubiquitous, holistic development & it encompasses long cherished principles and values of mutual collaboration, self-reliance and swadeshi. Based on the concept of 'Antyodaya', the basic purpose of Cooperatives in Madhya Pradesh has been the socio-economic development of all citizens in general and the weaker sections in particular. However, innovation needs to be brought in to generate employment in new areas while making the Cooperative movement stronger and more valuable for the development of the last mile people, making working of Cooperatives more efficient and forming primary Co-operatives in new sectors.

This policy will pave the way for Cooperatives to become a widespread movement in the State and the objectives of "Aatma Nirbhar Madhya Pradesh" and "Sahakar se Samriddhi" will be accomplished, bringing the ideal of "Aatma Nirbhar Bharat" closer to reality.

The objective of the Cooperative policy is to facilitate all-around development of Cooperative institutions of the Madhya Pradesh. This policy aims at providing necessary support, inspiration and assistance to the Cooperative institutions so that they can take the shape of such Cooperatives formed in an autonomous, self-reliant, and democratic manner, which are accountable to their members and thus promote economic growth. A series of meetings and consultations were organized with prominent scholars and experts on formulating draft of Cooperative policy. The policy is under formulation by MPSPPC and the Cooperative department, Govt. of Madhya Pradesh.

Madhya Pradesh Semi-conductor Investment Policy 2022

This policy aims to attract investments for creating a world-class end to end semiconductor cluster ecosystem in the state to cater to the demand for Compound Semiconductors/ Silicon Photonics (SiPh)/ Sensors (including MEMS) Fabs. The aim is to create an integrated value chain comprising Fabs and semiconductor ATMP/OSAT facilities. The Semi-conductor policy has adopted the following strategy and developed a roadmap for the way forward:

- Provision of land for the establishment of FAB, ATMP-OSAT and Advanced training/Skilling centres equipped with modern equipment.
- To incentivize the sector through various benefits.
- Handholding of investors during the set-up stage and continue to assist them after the setup has been completed by a Nodal Agency comprising experts from Industry, academia/ research organizations and State administration.
- Collaboration with multilateral lending agencies and sovereign wealth funds to tackle the issue of viability Gap Funding in prospective projects.

The Department of Industry Policy and Investment Promotion (DIPIP) will be the nodal agency for the implementation of the Madhya Pradesh ATMP-OSAT Investment Policy- 2022.

The policy draft is ready and is being reviewed by Dr. V. K. Saraswat, Member, NITI Aayog, Delhi and concerned departments.

Road Map for boosting Bioeconomy of the State

The Government of Madhya Pradesh is committed to socio-economic development of the state as well as conservation and sustainable use of its rich biodiversity in order to expand livelihood opportunities. In the recent decades, Life science has emerged as an integral part of the healthcare ecosystem. Unprecedented crisis that arose as a result of the COVID-19 pandemic has brought innovation in medicine and investments in R&D at the forefront. Role of the vaccine industry has been exceptional in supporting social and economic recovery. Bioeconomy is worth US $ 80.7 Billion and contributes to 2.7% of overall GDP of India.

Matching the global trends, the life science sector holds tremendous opportunities of growth. India aspires to have a Bioeconomy of US $ 150 Billion by 2025 as part of its US $ 5 Trillion economy.

Madhya Pradesh has been a consistent performer nationally in developmental parameters. Madhya Pradesh aspires to leapfrog to become a US $ 550 billion economy (41.30 lakh crore) by 2025 and contribute to the greater cause of building the nation's economy to US $ 5 Trillion. Recently, Government of Madhya Pradesh has launched a roadmap "Contribution of Madhya Pradesh in National Goal of US $ 5 Trillion Economy" for achieving its targets by 2025. Development of bioeconomy has been identified as one of the major actionable items.

Therefore, the exercise of defining strategy for development of the Bioeconomy of Madhya Pradesh has been initiated by Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission (MPSPPC) in coordination with relevant line departments of government, academia, industry and in consultation with relevant stakeholders.

The major focus of the strategy for developing Bioeconomy of Madhya Pradesh has been towards creating a robust support ecosystem for nurturing innovations, skilled manpower, academia, R&D facilities and industrial ecosystem.

Devaranya Yojna

In order to promote AYUSH in Madhya Pradesh and to link it with employment, the Government has formulated the 'Devaranya Scheme'. The scheme has been made to provide employment to the people living in the tribal areas of the state. A complete value chain for the production of AYUSH medicines will be developed in the state through Devarnya Yojana. Self-help groups will also play an important role in this work. AYUSH Department, Forest Department, Rural Development Department, Horticulture Department, Tourism Department, Agriculture Department, Micro Small and Medium Enterprises Department, Industrial Policy and Investment Promotion Department and Tribal Affairs Department will work together in mission mode. AYUSH and tourism will also be brought together.

The key features of the Devaranya Yojana are as below:

- It aims at increasing the share of medicinal plants cultivation in state's agriculture through convergence and market linkages.
- It focuses on mainstreaming Tribal population into the economic development of the State.
- Devaranya yojana aims to provide livelihood and increase income of the marginal farmers through utilising traditional knowledge.
- This also contributes in conservation of traditional medicinal plants in the state.

Major Events

Budget pe Charcha

A discussion on Madhya Pradesh Budget for the Financial Year 2022-23 was organised on 14 March, 2022. The event was attended by all Cabinet Ministers and MLAs of the State. The program began with the address by the Hon'ble Chief Minister on the budget and the vision behind the budget. Further, a detailed presentation was made by the Principal Secretary, Finance Department. Hon'ble Vice Chairman, MPSPPC discussed with Cabinet Minister and MLAs of Madhya Pradesh on "Aatma-Nirbhar Madhya Pradesh Ka Budget" in the event.

Civil Society Organizations' (CSO) Conclave

The CSO conclave was organised by AIGPPA in coordination with MPSPPC and Jan Abhiyan Parishad (JAP) on 8 and 9 April 2022 at Kushabhau Thakre International Convention Centre, Bhopal. The objective of the conclave was to explore the possibilities of collaboration between CSO's & Government Departments.

The CSO conclave highlighted that there is a need to define collaboration among all development agencies in order to mark clear roles and responsibilities of government, CSOs, Knowledge partners and other agencies. Further, the CSO conclave also discussed the advanced tools and technologies available to make the collaboration more effective.

A detailed report of the CSO conclave has been prepared by AIGPPA and shared with all participants. A follow up action plan has been

chalked out for facilitating CSO led monitoring and evaluation of the Government welfare projects. Apart from this, a CSO working group has also been formed in order to organise capacity building programs for grassroots organisations working on SDG goals in the state. The issue of promoting new generation developmental journalist was also discussed at length. The follow up plans are being prepared by AIGPPA, JAP and MPSPPC.

Interactive Session

Chintan-2022 – two days workshop was organised on 22-23, April 2022. at Pachmarhi. The Finance Department made a presentation on "Contribution of Madhya Pradesh in National Goal of US $ 5 trillion economy".

AYUSH Investment and Innovation Summit (20-22 April, 2022) at Gandhinagar, Gujarat

Hon'ble Prime Minister of India inaugurated Global AYUSH Investment and Innovation Summit (20-22 April 2022) at Gandhinagar, Gujarat.

Hon'ble Vice Chairman, MPSPPC participated as a Resource Person in the round table discussion on 20 April 2022. Shri Abhishek Singh (CEO, SMPB, MP) represented the state in the session "Govt./UTs Initiatives : Incentives, Innovations & Policies" and made a presentation on Devaranya Scheme on 21 April 2022. This scheme aims to provide livelihood to marginal tribal communities of MP through promoting the farming of medicinal plants.

Guest Speaks

Spearheading Urbanization through Policy & Planning

Mr. Hitesh Vaidya
Director,
National Institute of
Urban Affairs,
New Delhi.

India is gearing up to take its rightful place as one of the world's largest economies. The urbanization process in India has great implications for quality of life, public health, economic vitality, and sustainable development. To radically change how Indian cities function for the better, it is necessary to plan for the future. The next 15-20 years present a tremendous challenge but also an opportunity to innovate and leapfrog towards addressing India's struggle related to adequate and affordable housing, public transportation, water supply, waste, and waste-water treatment.

With the proliferation of data and the emergence of novel technologies, the potential for innovation is manifold. The quantum leap in the innovation and technology field has provided an exciting platform for making rapid strides in providing better quality municipal services to citizens. Coordinated, Converged, and Collaborative efforts with respect to infrastructure, planning, development, and deployment have to be an integral part of any innovation especially given the multiplicity of institutions within India's urban ecosystem.

Innovation and technology approach across the urban spectrum is turning out to be the differentiating factor to achieve scale and sustainability. There is an urgent need today for implementable research and expertise in the urban sector.

Today's urbanization calls for updating and upgrading not just policies and responses but also, the need for institutions of governance to come up with appropriate tools to handle the demands of the 21st century. The only way to address India's urban challenges is to ensure that the underlying governance principles of participation, decentralization, autonomy and accountability of representative urban local governments are strongly upheld.

"Our greatest ability as humans is not to change the world, but to change our selves"

MPSPPC Participation

List of Meetings/VCs and Conferences

- Participation in 7th National Cooperative Conference of Sahakar Bharti at Lucknow to interact with Subject Matter Experts of Cooperative Sector.
- Meeting with Dr. S.R. Rao, Vice President, Balaji Vidypeeth University on Life Sciences policy, in Bengaluru, Karnataka.
- Discussion on draft Semi-Conductor Investment policy of Madhya Pradesh under chairmanship of Shri. V.K. Saraswat, Member, NITI Aayog in New Delhi.
- Meeting with Shri. Akhilesh Gupta, Senior Advisor, Ministry of Science and Technology, Government of India on zero draft of Madhya Pradesh Science Technology and Innovation policy in New Delhi.
- Meeting with Mr. Satish Marathe, Director, RBI on Co-operative Policy in Mumbai, Maharashtra.
- Meeting with Shri. Raman Ahuja, Value Chain Specialist, UNFAO on draft of Madhya Pradesh Millet Mission, in New Delhi.

Miscellaneous

- MPSPPC is supporting the Northern Coal Field Limited in setting up of Coal Gasification Plant in Madhya Pradesh. This does not only help in contributing to Nation's goal but creates a clean energy source for the State.
- MPSPPC is continuously working on improving logistics infrastructure and reducing the bottleneck so that current warehousing facilities and inland container depot (ICD) can be supported and cater solutions to their problem.
- Data collection for the Regional Consultation with States/UT on welfare of Transgender Persons.
- Meeting with NGOs and Departments of MP and GoI for Water Policy.
- Meetings with Farmer Welfare and Agriculture Development department and Mandi Board were held for MP Millet Mission.
- Meeting with officers of UADD, WRD, and MP Jal Nigam for departmental interaction and follow-ups.
- MPSPPC, collaboration with Fisheries Department, Govt. of Madhya Pradesh, developed a project for developing Parvati reservoir as a Centre of Excellence in fish production on PPP model.
- Internship programme at MPSPPC is continued.

MPSPPC Team

Yogendra Shrivastava

Rishi Maurya

Prachi B. Joshi

Rajkamal Gautam

Pankaj k. Naik

Dr. Hemant Singh

Shivam K Kantharia

D S Rawat

Yograj Kose

Rakshinda Ali

Sanjay Durge

Ashish Kumar Soni

S.N. Sharma

Anish Gajbhiye

Gaurav Kushwah

Keshav Chaudhary

Ravi Soni

Tarun Janoriya

Hemant Dahouliya

MPSPPC Policy Team

Abhiuday Jha

Abhishek Bhargav

Abhishek Malviya

Achyut Joshi

Dr. Akanksha Chand

Amiya Shanker

Asit Prakash

Bhanu Bitra

Gaurav Thapak

Dr. Ish Gupta

Kanhaiya Samadhiya

Komal Mishra

Kumar Ratan

Dr. Neha Gupta

Prashansa Dixit

Preeti Tiwari

Rajdeep Singh

Sumita Soni

Sunil Kumar

Vipul Singhal

Vivekanand Jha

CONTENT

Monitoring, Evaluation and Co-ordination 03
- State Project Review (Pragati)
- Aspirational Block Programme
- Sustainable Development Goals

Board Meeting 04

Strategies and Reforms 05
- GSDP Task Force Report
- Strengthening Statistical System in Madhya Pradesh - Taskforce Report

Capacity Building 06
- Exposure visit to Odisha
- Workshop on Gender Responsive Budgeting (GRB)

Policy Advisory and Research 07
- Science, Technology & Innovation Policy
- Ensuring Last-mile delivery of Financial Services through Micro ATMs
- Integrated Water Policy
- Madhya Pradesh Millet Mission
- Madhya Pradesh Co-operative Policy
- Madhya Pradesh Semi-conductor Investment Policy
- Road Map for boosting Bio-economy of the State
- Devaranya Scheme

Major Events 11

Guest Speaks 13

MPSPPC Participations 14

Publications 16

Compiled & Edited by :
Prachi Bohare Joshi, Kumar Ratan
Madhya Pradesh State Policy
& Planning Commission (MPSPPC)

Designed by :
Prashansa Dixit
Madhya Pradesh State Policy
& Planning Commission (MPSPPC)

Publication- Reports

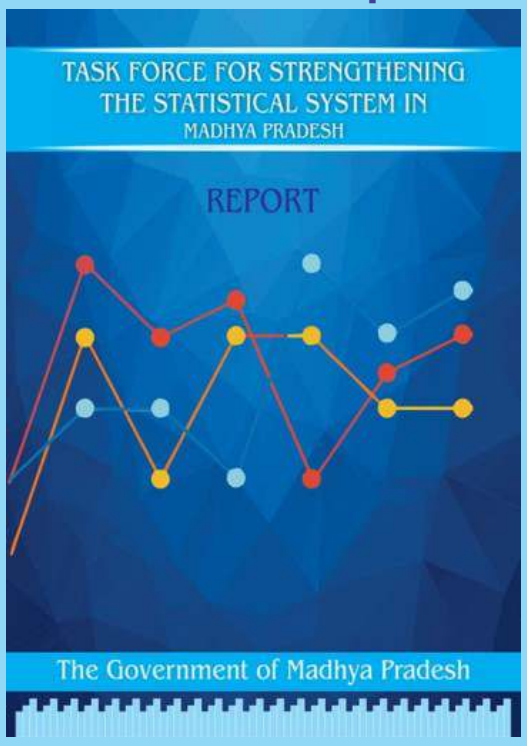

Report: Task Force For Strengthening the Statistical System in MP (click here)

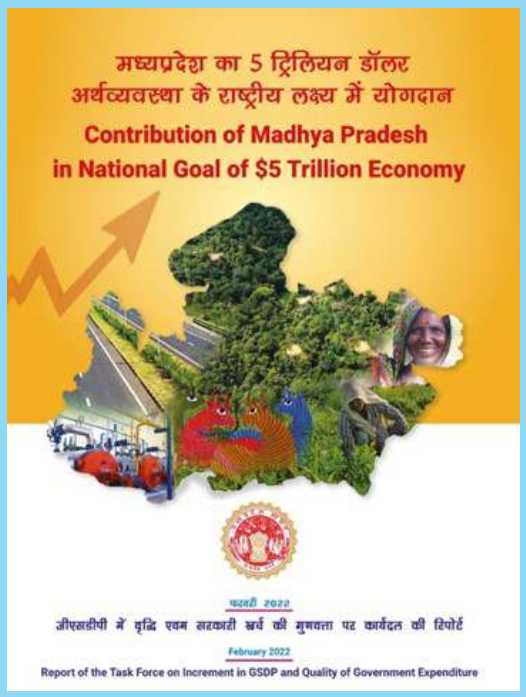

Report: Contribution of Madhya Pradesh in National Goal of $5 Trillion Economy (click here)

Madhya Pradesh State Policy & Planning Commission (MPSPPC)
Rajiv Gandhi Parisar, Plot no. 35, Shyamala Hills, Bhopal (M.P.) – 462002
Telephone: +91 755-2551456, 2551564, 2551135
Email: spb@nic.in **Website:** www.mpplanningcommission.gov.in, **Twitter :** @mpniti